



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Monday, 20 Jan, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 04 Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति	वार्षिक कैलेंडर, संसद में हर साल कम से कम 100 बैठकें होनी चाहिए: ओ'ब्रायन
Page 09 Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी	भारतीय क्रिप्टोग्राफी अनुसंधान क्वांटम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार
Page 09 Syllabus : : प्रारंभिक तथ्य	जलकुंभी केन्याई झील पर मछुआरों की आजीविका के लिए खतरा
Page 11 Syllabus : GS 2 : शासन	दिवालियापन समाधान को फिर से तैयार करना
समाचार में	2047 तक स्वस्थ राष्ट्र के लिए भारत का रोडमैप
Page 10 : संपादकीय विश्लेषण: Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	कट्टरपंथी सरकारों में उछाल, लोकतंत्र की उम्मीद



Page 04: GS 2: Indian Polity

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन ने संसद सत्र के लिए सरकार की अल्प सूचना की आलोचना की और कम से कम 100 बैठकों वाले वार्षिक कैलेंडर का आग्रह किया।

Annual calendar, at least 100 sittings every year must in Parliament: O'Brien

The Hindu Bureau

NEW DELHI

Criticising the government for shrinking the time between the notice announcing the Parliament session and its commencement, the Trinamool Congress's Rajya Sabha leader Derek O'Brien on Sunday urged the government to come up with an annual calendar for Parliament and mandatorily have at least 100 sittings in a year.

"If schools and colleges can set up their calendars way in advance, why can't Parliament," Mr. O'Brien asked.

Mr. O'Brien said added that the short notice affects the preparedness of members. "Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha are elected not just to legislate, but also to hold the government accountable, scrutinise its actions, and debate matters of national importance. These responsibilities will be fulfilled far better with a structured and predictable Parliamentary calendar," he said.

संसद सत्र के लिए कम समय की सूचना से जुड़े मुद्दे

तैयारी के लिए अपर्याप्त समय:

- o कम समय की सूचना के कारण सांसदों के पास महत्वपूर्ण बहस और चर्चाओं के लिए तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचता है।
- o इससे विधेयकों और प्रस्तावों की सतही जांच हो सकती है, जिससे विधायी कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

🔷 कम जवाबदेही और जांच:

- o अपर्याप्त समय के कारण, संसद सदस्य सरकार को प्रभावी ढंग से जवाबदेह नहीं ठहरा पाते हैं।
- o राष्ट्रीय मुद्दों पर संसदीय बहसें जल्दबाजी में की जाती हैं, जिससे विस्तृत जांच की संभावना कम हो जाती है।

सदस्यों की भागीदारी पर प्रभाव:

- o कम समय की सूचना के कारण सांसदों का कार्यक्रम बाधित होता है, खासकर उन सांसदों का जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े होते हैं।
- o तैयारी के लिए समय की कमी सदस्यों और उनके द्वारा सेवा प्रदान करने वाले लोगों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता दोनों को प्रभावित करती है।

सार्वजनिक अविश्वास:

- o अप्रत्याशित संसदीय कार्यक्रम सरकार के कामकाज में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं।
- o नागरिक पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं, और अचानक सत्र की घोषणा से विधायी प्रक्रिया में हेरफेर होने की चिंता बढ़ सकती है।





विधायी अव्यवस्थाः

- o जब सत्रों की योजना पहले से नहीं बनाई जाती है, तो संरचित कार्य की कमी होती है, जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों की प्राथमिकता प्रभावित होती है।
- o पूर्वानुमानित कैलेंडर की कमी के परिणामस्वरूप अव्यवस्थित और अव्यवस्थित संसदीय कार्यवाही होती है।

आगे की राह: संरचित संसदीय कैलेंडर

🏓 वार्षिक संसदीय कैलेंडर की शुरुआत:

- o सरकार को संसद के लिए एक वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करना चाहिए, जिससे सभी हितधारक आगे की योजना बना सकें।
- o इसमें अपेक्षित सत्र तिथियां, चर्चा के विषय और महत्वपूर्ण विधायी मामले शामिल हो सकते हैं।

न्यूनतम 100 संसदीय सत्रों को अनिवार्य बनाना:

- o उचित विधायी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वर्ष कम से कम 100 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
- o यह सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने, बहस करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए पर्याप्त समय हो।

सत्र नियोजन में सुधार:

- o नियोजन में सत्रों के बीच पर्याप्त अंतराल की अनुमित होनी चाहिए, जिससे सदस्यों को तैयारी और निर्वाचन क्षेत्र के काम के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- o पूर्वानुमानित सत्र संरचना बहस और विचार-विमर्श की गुणवत्ता में भी सुधार करती है।

निष्कर्ष

 एक पूर्वानुमानित कैलेंडर स्थापित करके, संसद अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनता के हितों की सेवा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकती है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: संसद सत्रों के लिए अल्प सूचना घोषणाओं से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एक संरचित वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से संसद के कामकाज और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए आगे का रास्ता सुझाएँ। (150 Words /10 marks)



Page 09: GS 3: Science and Technology

समाचार में भारत में क्रिप्टोग्राफी के बढ़ते क्षेत्र - डेटा की सुरक्षा के लिए इसके महत्व, तथा क्वांटम कंप्यूटिंग और उभरती एन्क्रिप्शन तकनीकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई है।

Indian cryptography research gears up to face the quantum challenge Areas where Indian researchers are working extensively include communication complexity, the amount of communication required to complete a computational task; proof complexity, the computational resources required to prove or disprove statements and algebraic coding theory











- क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सादे टेक्स्ट को अपठनीय सिफरटेक्स्ट में परिवर्तित करके जानकारी को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।
- 🖈 इसका मुख्य लक्ष्य सिस्टम सुरक्षा सुनिश्चित करना और संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुँच को रोकना है।
- गुप्त संदेश भेजने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें जूलियस सीज़र के सिफर और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई एनिग्मा प्रणाली जैसे उल्लेखनीय ऐतिहासिक उदाहरण हैं।

क्रिप्टोग्राफी का महत्व

- 🕩 क्रिप्टोग्राफी का उपयोग जटिल समस्याओं को हल करके डेटा की सुरक्षा के लिए किया जाता है।
- 🕩 इन समस्याओं को हल करना कठिन और महंगा होता है।
- इसका लक्ष्य विरोधियों को एन्क्रिप्ट की गई जानकारी को डिकोड करने से रोकना है।
- बड़ी कंप्यूटिंग शक्ति वाले लोग भी आसानी से कोड नहीं तोड़ सकते।
- 🕩 क्वांटम कंप्यूटर सहित कंप्यूटिंग में प्रगति के बावजूद क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
- जैसे-जैसे कम्प्यूटेशनल शक्ति बढ़ती है, सुरिक्षत रहने के लिए क्रिप्टोग्राफी को विकसित होना चाहिए।
- मजबूत क्रिप्टोग्राफ़िक सिस्टम कठिन समस्याओं का उपयोग करते हैं जिन्हें कंप्यूटर के लिए हल करना मुश्किल होता है।
- 🕩 मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि डेटा दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं से सुरक्षित और निजी बना रहे।

चुनौतियाँ और धीमी प्रगति

- क्रिप्टोग्राफी अपनी जटिलता और जटिलता सिद्धांत और क्रिप्टोग्राफी के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण धीमी गित से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र है।
- भारत में अनुसंधान संचार जिटलता, प्रमाण जिटलता और बीजगिणतीय कोडिंग सिद्धांत जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना है।

क्रिप्टोग्राफी कुंजियाँ और उनका कार्य

- क्रिप्टोसिस्टम का मूल कुंजी है, जो डेटा को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गुप्त मान है।
- सार्वजिनक-कुंजी क्रिप्टोग्राफी जैसी आधुनिक प्रणालियाँ दो कुंजियों का उपयोग करती हैं: एक सार्वजिनक कुंजी जो प्रेषक के साथ साझा की जाती है और एक निजी कुंजी जो प्राप्तकर्ता द्वारा रखी जाती है।
- एन्क्रिप्शन को आसान बनाने के लिए वन-वे फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है लेकिन कुंजी के बिना डिक्रिप्शन बहुत मुश्किल होता है।

उभरते हुए अनुसंधान और चुनौतियाँ

- क्रिप्टोग्राफी में दो विघटनकारी अनुसंधान क्षेत्र होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन हैं, जो एन्क्रिप्ट किए गए डेटा पर गणना की अनुमित देता है, और क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी, जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम क्वांटम कंप्यूटिंग खतरों का सामना कर सकते हैं।
- भारतीय शोधकर्ता इन क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, और सरकार राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और क्वांटम संचार विकास सिहत क्रिप्टोग्राफी अनुसंधान को वित्त पोषित कर रही है।

भारत में क्रिप्टोग्राफी का भविष्य





- भारत क्रिप्टोग्राफी अनुसंधान में आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से क्वांटम संचार और डेटा सुरक्षा में, सरकार के समर्थन और विभिन्न
 संस्थानों के सहयोग से।
- 🔷 जैसे-जैसे संवेदनशील डेटा बढ़ता जाएगा, एन्क्रिप्शन का महत्व बढ़ता जाएगा, खासकर क्लाउड स्टोरेज में।





Daily News Analysis

Page 09: Prelims Fact

केन्या की लेक नैवाशा में मछुआरे आक्रामक जलकुंभी के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जो मछलियों की आबादी को नुकसान पहुँचाती है।

एक स्टार्ट-अप, हयापैक, पौधे की कटाई करने के लिए उनके साथ साझेदारी करता है, इसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदल देता है, जिससे पर्यावरण और आजीविका दोनों को मदद मिलती है।

वाटर हाइसिंथ:

- यह दक्षिण अमेरिका में अमेजॅन बेसिन का एक आक्रामक जलीय पौधा है।
- विशेषताएँ: पानी पर तैरता है, इसमें बडी, चमकदार हरी पत्तियाँ, बैंगनी फूल होते हैं।
- फैलाव: तेज़ी से बढ़ता है, घने मैट बनाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है, मछली की आबादी को बाधित करता है, और पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
- आर्थिक प्रभाव: जल परिवहन, मछली पकड़ने और कृषि को बाधित करता है।
- नियंत्रण के तरीके: यांत्रिक निष्कासन, जैविक नियंत्रण (कीटों का उपयोग करके), रासायनिक उपचार।

समाचार में स्थान: लेक नैवाशा

- लेक नैवाशा केन्या में एक लोकप्रिय मीठे पानी की झील है।
- 🟓 यह 10 वर्षों से अधिक समय से आक्रामक जलकुंभी से प्रभावित है।
- 🕩 जलकुंभी के कारण मछलियों की संख्या में कमी आई है, जिससे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है।
- पहले मछुआरे प्रतिदिन 90 किलो तक मछिलयाँ पकड्ते थे, लेकिन अब यह संख्या केवल 10-15 किलो रह गई है।
- जलकुंभी के आक्रमण के कारण झील को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मछली पकड़ने, परिवहन और पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।



Water hyacinth threatens the livelihoods of fishers on Kenyan lake

Associated Press

For someone who fishes for a living, nothing says a bad day like spending over 18 hours on a lake and taking home nothing.

Recently, a group of fishermen were stranded on Kenya's popular Lake Naivasha for that long and blamed the water hyacinth that has taken over large and the strength of the strength of the strength of the water hyacinth that has taken over large and the strength of the stren

estimated in a 2023 study that the invasion of water hyacinth in Kenyan

The water hyacinth is native to South America and was reportedly introduced to Kenya in the 1980s 'by tourists who brought it as an ornamental plant'

lakes – including Lake Victoria, Africa's largest – has led to annual losses of between \$150 million and \$350 million in Kenya's fishing, transport, and tourism sectors

largest — has led to annual losses of between \$150 million and \$350 million in Kenya's fishing, transport, and tourism sectors.

Sectors.

Lake Naivasha know that well. "Previously we would catch up to 90 kg of fish per day, but nowadays we get between 10 kg and 15 kg." Macharia said. This means daily earnings have dropped from \$210 to \$35.

There are several ways to deal with the plant, including physically removing it, Ocholla said. Another method is introducing organisms that feed on it. Or chemicals can be sprayed to kill the plant, because the plant of the company of the plant of the company is the company in the company is made and the company is trying to use one problem, the hyacinth, "to solve the plantic was a project at Egerton University in Kenya. HyaPak tounder Joseph Nguthiru said the company is trying to use one problem, the hyacinth, "to solve the plastic waste popping that the plantin," to solve the plastic waste poping the sheet of the plantin, "to solve the plastic waste poping the sheet of the plantin," to solve the plastic waste poping the sheet of the plantin, and sun-dry it for a negotiable fee. Then it is transported to a HyaPak facility to be converted into biodegradable paper material.

The company works with 50 fishers at Lake Naivasha and processes up to 150 kg of water hyacinth per week, converting it to 4,500 biodegradable paper, and to the planting it.



Page 11: GS 2: Governance

यह लेख भारत की दिवालियापन प्रणाली से जुड़ी समस्याओं, देरी, विशेषज्ञता की कमी और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालता है।

Recasting insolvency resolution

he Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) is one of India's most significant economic reforms, introduced to address the challenges of insolvency resolution in a structured and time-bound manner.

At the time of its introduction, the IBC was seen as an important tool that would help India's standing in the business world and bring bad borrowers and big defaulters to book. Yet, as the law matured, certain issues have cropped up that demand attention, particularly regarding institutional capacity and procedural efficiency. The recent Supreme Court of India judgment in Jet Airways (State Bank of India & Ors. vs The Consortium of Mr. Murari Lal Jalan and Mr. Florian Fritsch & Anr.) has laid bare the many structural infirmities that are plaguing India's insolvency

A double burden

The effective implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) hinges on the performance of the National Company Law Tribunal (NCLT) and its appellate body, the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT). These tribunals face the dual burden of handling corporate insolvencies under the IBC and cases under the Companies Act. This institutional architecture, however, suffers from what might be termed "temporal disjunction".

Conceived in 1999 based on the Eradi Committee's recommendations and operationalised in 2016, the NCLT's structure reflects the economic realities of a bygone era, leaving it ill-equipped to meet contemporary demands. With a sanctioned strength of 63 members - many of whom divide their time across multiple benches - the NCLT has become a bottleneck for insolvency resolutions and corporate transactions such as mergers and amalgamations.



is an advocate in the Madras High Court



Saai Sudharsan Sathiyamoorthy

is an advocate in the Madras High Court Compounding the issue, several NCLT benches do not operate for the full working day, even when not tasked with handling cases from other benches.

As a result, delays have worsened. According to the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), the average time for insolvency resolutions increased to 716 days in FY2023-24, up from 654 days in FY2022-23. This is despite the Supreme Court's repeated calls for adherence to the specific timelines provided in IBC, including in the Jet Airways case, where the Court has stated that the "NCLTs/NCLATs need to be sensitised of not exercising their judicial discretion in extending the timelines...in such a way that it may make the Code lose its effectiveness thereby rendering it

The need for domain expertise

obsolete".

The current framework's deficiencies are manifest across other dimensions. What stands out the most is the qualitative dimension of institutional capacity. The current method of appointment ignores the need for domain experience. As the Court noted in the Jet Airways case, "Members often lack the domain knowledge required to appreciate the nuanced complexities involved in high-stakes insolvency matters...". This creates a paradox where an institution tasked with resolving complex cases is hindered by a lack of specialised knowledge.

However, the problems run deeper than capacity limitations. There is also the bureaucratic labyrinth. There is no effective system in place before the NCLTs for urgent listings. And as noted by the Supreme Court, the staff of the Registry is given wide powers to list or not to list a particular matter. Perhaps most troubling is what the Court has termed a "growing tendency" among NCLT and NCLAT members to ignore or defy its orders, which threatens the very foundation of India's judicial hierarchy.

This is not merely about institutional efficiency. It is about institutional integrity.

Sparse use of alternatives

The procedural framework further exacerbates these constraints. The requirement for a mandatory hearing for all applications including for progress reports, which is not in any way necessary from the standpoint of natural justice, results in considerable delays. The limited use of alternative dispute settlement methods adds to the problems of an already overworked system.

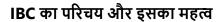
Various jurisdictions across the globe contend with similar challenges pertaining to institutional capacity and procedural efficiency.

Nevertheless, the magnitude of India's scale, its endemic corruption and its economic ambitions necessitate solutions that transcend mere incremental enhancements. The recent reform proposals, including the initiative for mandatory mediation prior to the submission of insolvency applications, present a degree of optimism.

Further, there needs to be a hybrid model that values judicial experience and domain expertise. Also, the time is ripe for procedural innovations that go beyond piecemeal changes. The creation of specialised benches for different categories of cases could enhance both efficiency and expertise and ensure that mergers and amalgamations are cleared in time.

Pertinently, infrastructure must not remain an afterthought. Adequate courtrooms and a qualified, permanent support staff are critical to sustaining these institutions within the broader economic framework. Above all, India's insolvency regime must evolve beyond mere debt resolution to serve as a proactive driver of economic rejuvenation, especially as the country aims to attract greater foreign investment. At this very important point in time, the choice is clear. The time for a bold reimagining is now.









- दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016, एक प्रमुख सुधार है जिसका उद्देश्य दिवालियापन को संरचित, समयबद्ध तरीके से हल करना है।
- 🔷 शुरुआत में, इसने खराब ऋणों और डिफॉल्टरों के मुद्दों को संबोधित करके भारत की वैश्विक व्यावसायिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया।
- हालाँिक, जैसे-जैसे कानून परिपक्क हुआ, संस्थागत क्षमता और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं से संबंधित चुनौतियाँ सामने आईं, जिन्हें
 विशेष रूप से जेट एयरवेज मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया।

संस्थागत ढांचे में चुनौतियाँ

🟓 न्यायाधिकरणों पर बोझ:

- o राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और इसकी अपीलीय संस्था, एनसीएलएटी, आईबीसी के तहत दिवालियापन के मामलों और कंपनी अधिनियम के तहत मामलों को संभालती है।
- o यह दोहरी भूमिका एक महत्वपूर्ण बैकलॉग बनाती है, जिससे समाधान धीमा हो जाता है।

एनसीएलटी की पुरानी संरचना:

- o एनसीएलटी की संरचना, जिसे 1999 में डिज़ाइन किया गया था और 2016 में चालू किया गया था, वर्तमान आर्थिक मांगों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- o केवल 63 स्वीकृत सदस्यों के साथ, जिनमें से कई कई बेंचों में काम कर रहे हैं, न्यायाधिकरण आधुनिक मामलों के भार को संभालने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है।

अकुशल संचालन:

- o कुछ NCLT बेंच पूरे कार्य दिवसों में काम नहीं करते हैं या अन्य बेंचों के मामलों को संभालने में लगे रहते हैं।
- o परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023-24 में दिवालियेपन समाधान के लिए औसत समय बढ़कर 716 दिन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 654 दिन था।

डोमेन विशेषज्ञता और अखंडता में कमियाँ

डोमेन ज्ञान की कमी:

- o न्यायाधिकरण के सदस्यों में अक्सर जटिल दिवालियेपन मामलों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी होती है।
- o सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज मामले में इस पर जोर दिया, जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

नौकरशाही चुनौतियाँ:

- o तत्काल लिस्टिंग के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है, और रजिस्ट्री कर्मचारियों के पास मामलों के प्रबंधन में अत्यधिक विवेकाधिकार है।
- o सुप्रीम कोर्ट ने NCLT/NCLAT सदस्यों द्वारा उसके आदेशों की अवहेलना करने के उदाहरणों पर ध्यान दिया, जिससे न्यायिक अखंडता को खतरा है।

प्रक्रियागत अक्षमताएँ





🔷 अनिवार्य सुनवाई:

- o प्रगति रिपोर्ट सहित सभी आवेदनों के लिए सुनवाई की आवश्यकता, अनावश्यक देरी का कारण बनती है।
- o वैकल्पिक विवाद समाधान का सीमित उपयोग:
- o प्रणाली वैकल्पिक तरीकों का कम उपयोग करती है, जिससे पहले से ही बोझिल ढांचे पर दबाव बढ़ जाता है।

सुधार के लिए प्रस्तावित समाधान

अनिवार्य मध्यस्थताः

o दिवालियापन आवेदनों से पहले अनिवार्य मध्यस्थता शुरू करने से न्यायाधिकरणों पर बोझ कम हो सकता है।

विशेष पीठ:

o विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए विशेष पीठ बनाने से दक्षता और विशेषज्ञता में सुधार हो सकता है।

🟓 बुनियादी ढाँचा और स्टाफ़िंग:

o न्यायाधिकरण के संचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त न्यायालय और योग्य, स्थायी कर्मचारी आवश्यक हैं।

हाइब्रिड मॉडल:

o जटिल दिवालियापन मामलों के लिए न्यायिक अनुभव को डोमेन विशेषज्ञता के साथ संयोजित करने वाला एक हाइब्रिड दृष्टिकोण आवश्यक है।

निष्कर्ष

- भारत की दिवालियापन व्यवस्था को ऋण समाधान से आगे बढ़ना चाहिए और आर्थिक विकास के चालक के रूप में काम करना चाहिए।
- विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्षमता, प्रक्रियात्मक दक्षता और बुनियादी
 ढाँचे में साहिसक सुधार आवश्यक हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: समय पर समाधान सुनिश्चित करने में भारत की दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इसकी संस्थागत क्षमता और प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार के उपाय सुझाएँ। (250 Words /15 marks)



In News: India's Roadmap to a Healthy Nation by 2047

2047 तक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने की भारत की आकांक्षा इसकी आबादी के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर निर्भर करती है।

 इसे प्राप्त करने के लिए, 2025 तक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली उभरनी चाहिए, जिसमें रोकथाम, न्यायसंगत उपचार और डिजिटल समाधानों के एकीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्वस्थ भारत के लिए मुख्य स्तंभ:

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी):

- o वित्तीय और सेवा लक्ष्य: यूएचसी का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और व्यापक सेवा कवरेज सुनिश्चित करना है।
- o संसाधन आवंटन: केंद्र और राज्य बजट पर ध्यान देने के साथ उच्च सार्वजनिक वित्तपोषण आवश्यक है।
- o स्वास्थ्य कार्यबल: प्रौद्योगिकी-सक्षम फ्रंटलाइन श्रमिकों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करके अत्यधिक कुशल डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए।

🕩 परिवर्तन के लिए एक टेम्पलेट के रूप में आयुष्मान भारत: मुख्य घटक -

- o उन्नत प्राथमिक देखभाल वास्तुकला।
- o कमजोर समूहों के लिए वित्तीय सुरक्षा।
- o उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना।
- o डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से एकीकरण।
- o डिजिटल स्वास्थ्य मिशन: महामारी विज्ञान खुफिया, कार्यक्रम निगरानी और सिस्टम एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण।

स्वस्थ भारत के लिए डेटा-संचालित निर्णय-निर्माण:

विघटित और एकीकृत डेटा सिस्टम:

o स्थानीय स्तर की जानकारी: सूचित, संसाधन-कुशल और इक्विटी-संचालित कार्यों के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर डेटा उपलब्ध होना चाहिए।

o महामारी विज्ञान संक्रमण:

- · गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बढ़ते बोझ के लिए रुझानों और जोखिम कारकों की सटीक ट्रैकिंग की आवश्यकता होती है।
- · जबिक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) प्रहरी साइटों के माध्यम से कुछ संक्रामक रोगों पर डेटा प्रदान करता है, जूनोटिक रोगों में तेजी से वृद्धि व्यापक और वास्तविक समय निगरानी डेटा की मांग करती है।

उन्नत निगरानी प्रणाली:

- o संक्रामक रोग: जूनोटिक खतरों सहित संक्रामक रोगों के लिए वास्तविक समय निगरानी। संक्रामक रोग निगरानी के केंद्र में बड़े डेटा विश्लेषण की आवश्यकता होगी।
- o तकनीक: अपशिष्ट जल निगरानी और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) निगरानी नियमित होनी चाहिए।
- o एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण: जलवायु संबंधी स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों में डेटा का एकीकरण।





स्वस्थ भारत के लिए डिजिटल रूप से एकीकृत स्वास्थ्य सेवा:

- रोगी-केंद्रित डेटा सिस्टम:
 - o इंटरऑपरेबिलिटी: निदान और उपचार डेटा सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुलभ होना चाहिए।
 - o चुनौतियाँ: निजी क्षेत्र के एकीकरण की कमी देखभाल की निरंतरता को बाधित करती है।
- सार्वजनिक-निजी सहयोग:
 - o अंतराल को पाटना: डिजिटल सिस्टम को प्राथमिक देखभाल और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों को जोड़ना चाहिए जो माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल देखभाल (जैसे PMJAY और राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम) का समर्थन करते हैं।
 - o इससे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य डेटा रिपॉजिटरी एकीकृत हो जाएँगी।
- ▶ AI-संचालित अंतर्दृष्टि: भारतीय स्वास्थ्य डेटा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग निदान और नैदानिक प्रबंधन को बढ़ा सकता है।
- सामुदायिक भागीदारी: डिजिटल उपकरण प्रकोप निगरानी के लिए क्राउडसोर्सिंग को सक्षम कर सकते हैं और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं।

निष्कर्षः

- 2047 तक स्वस्थ और उत्पादक आबादी की ओर भारत की यात्रा के लिए तत्काल और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
- 2025 तक, एक डिजिटल रूप से एकीकृत, डेटा-संचालित और सार्वभौमिक रूप से सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को जड़ जमाना चाहिए, जो राष्ट्र को उसके स्वास्थ्य लक्ष्यों की ओर अग्रसर करे।







Page : 10 Editorial Analysis A surge in radical governments, the hope of democracy

ne thing seems fairly certain now. If an Islamic radical group were to seize power by force, then the world will be willing to legitimise it and forgive its past deeds. But till the time such a group does not capture power, it will either be fought tooth and nail and/or treated like an enemy.

We had Afghanistan in 2021. We now have Syria in 2024.

When the Taliban captured power on August 15, 2021, 13 members of the United States troops were killed in an Islamic State (IS) suicide attack, and \$7.1 billion worth of U.S. weaponry was left behind in Afghanistan. However, the U.S. and the West as well as China and Russia bent backwards to work with the Taliban. The West justified this by saying that this would wean the Taliban away from supporting terrorism and help in the protection of women's and minorities' rights. They talked about "inclusive government" but democracy was not uppermost in their minds. The then UN Special Representative to Afghanistan, Deborah Lyons, even told the United Nations Security Council (UNSC) that the Taliban was 'misunderstood'.

Treated with kid gloves

The ultimate irony was how "karma" had come full circle. In the days preceding the Taliban's capture of Afghanistan, the "Troika Plus", of the U.S., China and Russia with Pakistan, had tried to coordinate their efforts in Afghanistan to keep India completely out and ignore our vital interests. In the UNSC, even an innocuous reference to the Heart of Asia Conference on Afghanistan was deleted from the draft statement because India was one of the countries attending

But when the events of August 2021 unfolded, India was the president of UNSC that month. Any text or resolution required India's concurrence. When UNSC Resolution 2593, after the Taliban takeover, was passed on August 30, India left its imprint particularly in the paragraph relating to Afghan soil not being used for terrorist activities. The express reference to terrorists and terrorist organisations in the UNSC Resolution 1267 sanctions list was inserted at India's behest, where it coordinated closely with the U.S. side. This was necessary to remove any ambiguity about Pakistani terrorist organisations associated with the ISIL (Daesh) and al-Qaeda, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed listed in 1267 - from using Afghan soil to launch terrorist attacks on India.

In December 2021, the UNSC allowed the Taliban to get donor money directly into its coffers. With no political will among the P-5 or the West to demand accountability for implementing UNSCR 2593, the Taliban soon



T.S. Tirumurti

was Permanent Representative Ambassador of India to the United Nations (UN), New York (2021-22) and President of the UN Security Council (UNSC) for August 2021

The last thing India needs is the revival of Islamic radicalism in

Bangladesh

denied girls school education, imposed restrictions on women, and stopped all moves for an inclusive government. Now, the world looks the other way.

Now, Syria and Bangladesh

And now Syria in 2024. We have just witnessed a radical Islamic leader Abu Muhammad al-Jolani or Ahmed al-Shaara of the Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) seize power, culminating in the toppling of Syrian President Bashar al-Assad. Al-Jolani was earlier leader of the al Qaeda in the region, with links to international terror groups. His radical outfit, the HTS, which was earlier an al Qaeda wing in Syria called the Jabhat al-Nusra, still features in the U.S. State Department list of terror groups. Mirroring what they did with the Taliban, the U.S. and the West have lined up behind the HTS and its leader. The first move of the U.S. was to remove the bounty of \$10 million on al-Jolani's head for his capture. Capturing power can help evade capture also.

This is wonderful news for Islamic terrorists and extremist groups gaining ground, especially in Africa such as in Mali, and adopting IS and al Qaeda techniques to topple governments. But the world is preoccupied with Ukraine and West Asia. Now, India has a situation brewing closer to home, in Bangladesh.

Even if the collapse of the elected government in Bangladesh has been largely due to an autocratic government stifling democratic forces and losing the plot, under the guise of supporting regime change, the U.S. clearly downplayed the interests of its "strategic" partner India. It is propping up the interim military-led government of Muhammad Yunus, which is seen as tolerating, even encouraging, Islamic radical groups in Bangladesh and is a threat to its minorities. The last thing India needs is the revival of Islamic radicalism in Bangladesh, where the last 16 years have seen the two countries and its peoples come closer in a variety of ways for mutual benefit.

When Sheikh Hasina and the Awami League came to power in 2008, it was seen as free and fair elections with a cleaned-up electoral list and the Bangladesh Army staying on the sidelines. The people overwhelmingly rejected the violent past of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) of Khaleda Zia and their Islamic radical partners such as the Jamaat-e-Islami. Just when one thought that the Jamaat-e-Islami stood discredited for siding with Pakistan in the 1971 war and rejected by the people of Bangladesh for causing mayhem and disrupting lives, the popular student protests of 2024 and the ensuing military coup have given them a fresh lease of life.

While there is no doubt that the Ansarullah Bangla Team (ABT) - affiliated to the Al Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS), the

Jamaat-e-Islami and its student wing, the Islami Chhatra Shibir, the Hefazat-e-Islam, the Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB) and the Islamic State-Khorasan Province (ISKP) have taken advantage of the situation, it is not as if the people of Bangladesh have embraced them wholeheartedly. Consequently, these radical groups have tried to shore up support for their extremist ideologies by attacking the minority communities, forcing the interim government to release Islamic extremists from prison (such as like Jashimuddin Rahmani, head of the ABT), and adopting shrill anti-India rhetoric, conflating the dismantling of Sheikh Hasina's legacy with attacks on India. India should be careful not to fall into this trap.

Religious hate has been on the rise around the world. It was when this writer was India's Permanent Representative to the UN that India brought up, for the first time, in 2021-2022, the rise of religiophobia against non-Abrahamic religions, including against Hindus, Sikhs and Buddhists. India condemned all forms of religious hate, whether in the U.S. and the West or in Bangladesh and the neighbourhood. While India may have taken its eye off the ball when it came to the Sheikh Hasina government, it cannot ignore Islamic extremism again rearing its head in Bangladesh and posing renewed danger to India's national security - something which New Delhi successfully prevented over the last 16 years.

The larger picture

However, for both sides to view the unfolding events purely through a religious lens - be it an Islamic lens or Hindu lens – would be a mistake. This has been counterproductive before and will be so now. In fact, Islamic radicals are baiting India, and, unfortunately, so are the officials who have been appointed as advisers to Mr. Yunus, precisely to polarise forces within their own country. On the other hand, India has the larger perspective in mind to protect its bilateral relations from damage. It has reiterated its readiness to do business with the interim government. India has removed most irritants in its bilateral relations in the last two decades, except maybe for the sharing of Teesta river waters. What is forgotten is that when Bangladesh Rifles (BDR) revolted in February 2009, just after the first clean elections of Bangladesh in December 2008, it was India which gave its rock solid support to the newly-elected government and helped save democracy.

It is in Bangladesh's own interest that this military coup does not translate into an Islamic coup and goes the way of Syria or Afghanistan. The silver lining is that, having tasted the power of democracy in 2008, and now in 2024, it will be difficult to put the clock back.





GS Paper 02 : अंतरराष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question: वैश्विक राजनीति में कट्टरपंथी समूहों को वैध बनाने से उत्पन्न चुनौतियों की जांच करें, तथा भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर इसके प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करें। (150 Words /10 marks)

संदर्भ:

 लेख में कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा सत्ता हथियाने के बाद उन्हें वैध बनाने के वैश्विक पैटर्न पर चर्चा की गई है - जिसमें अफ़गानिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश के लिए निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया है।

2021 में अफ़गानिस्तान: तालिबान का कब्ज़ा

- 15 अगस्त, 2021 को अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता हथिया ली। इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में
 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 7.1 बिलियन डॉलर का अमेरिकी हथियार पीछे छूट गया।
- तालिबान के विवादास्पद इतिहास के बावजूद, अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों ने उनके साथ मिलकर काम किया और इसे महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और आतंकवाद को हतोत्साहित करने के तरीके के रूप में उचित ठहराया।
- अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के अध्यक्ष के रूप में भारत ने यूएनएससी प्रस्ताव 2593 को प्रभावित किया तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफगािनस्तान की धरती का उपयोग आतंकवाद के लिए, विशेष रूप से भारत के खिलाफ, न किया जाए।
- प्रस्ताव में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों पर भी प्रकाश डाला गया।

तालिबान के साथ दुनिया भर में जुड़ाव का विकास

- ➡ दिसंबर 2021 में, UNSC ने जवाबदेही की मांग किए बिना तालिबान को सीधे दानकर्ता निधि देने की अनुमित दी।
- बाद में तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया और समावेशी शासन से इनकार कर दिया, लेकिन वैश्विक शक्तियों ने इन घटनाक्रमों को बड़े पैमाने पर अनदेखा कर दिया।

2024 में सीरिया: एक नया संकट

 2024 में, हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेता अबू मुहम्मद अल-जोलानी ने राष्ट्रपित बशर अल-असद को अपदस्थ करते हुए सीरिया में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।





- अल कायदा नेता के रूप में उनके अतीत और HTS को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद,
 अमेरिका और पश्चिम ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया।
- अमेरिका ने अल-जोलानी पर \$10 मिलियन का इनाम हटा दिया, जो सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद समूहों को वैध बनाने के पैटर्न को दर्शाता है।

बांग्लादेश में बढ़ता चरमपंथ

- बांग्लादेश में, मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सैन्य-नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यभार संभाला है, जो कथित तौर पर इस्लामी कट्टरपंथी समूहों को बर्दाश्त कर रही है।
- अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी), जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे समूह प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं,
 अल्पसंख्यकों को धमका रहे हैं और भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं।
- सैन्य तख्तापलट ने चरमपंथी विचारधाराओं के लिए एक मंच प्रदान किया है, जिसने 2008 से शेख हसीना की सरकार के तहत की गई प्रगति को उलट दिया है।

भारत की भूमिका और चिंताएँ

- भारत ने 2009 के बांग्लादेश राइफल्स विद्रोह सिहत महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान बांग्लादेश का समर्थन किया और दो दशकों से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है।
- बांग्लादेश में चरमपंथ का उदय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता है, जिसे इस मुद्दे को केवल धार्मिक चश्मे से देखने के जाल में फंसने से बचना चाहिए।
- भारत का ध्यान अपने द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा करने और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने पर बना हुआ है।

सावधानी की आवश्यकता

- वैश्विक रुझान संकेत देते हैं कि सत्ता पर कब्जा करने से कट्टरपंथी समूहों को वैधता मिलती है, जैसा कि अफगानिस्तान, सीरिया और संभावित रूप से बांग्लादेश में देखा गया है।
- बांग्लादेश के लिए, इस्लामी चरमपंथी शासन की ओर लौटना 2008 के बाद से उसकी लोकतांत्रिक प्रगति को खत्म कर देगा।
- वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत को, क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए उग्रवाद के पुनरुत्थान की निगरानी करनी चाहिए
 और उसका समाधान करना चाहिए।

निष्कर्ष

- सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद कट्टरपंथी समूहों को वैध बनाने की वैश्विक प्रवृत्ति लोकतंत्र और स्थिरता को कमज़ोर करती
 है।
- भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से पड़ोसी बांग्लादेश में उभरते खतरों का सक्रिय रूप से समाधान करना चाहिए।